

सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ कानून पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है लेकिन वक्फ संशोधन अधिनियम दो हजार पचीस के कुछ प्रावधानों को स्थगित भी कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज अपना निर्णय सुनाया। एक रिपोर्ट—

सरकार ने नामित अधिकारी को यह निर्णय लेने की अनुमति देने वाले प्रावधान पर भी रोक लगाई है कि क्या कोई वक्फ संपत्ति सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करती है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि कार्यकारी अधिकारी नागरिकों के अधिकारों का निर्धारण नहीं कर सकते, क्योंकि यह शक्तियों के विभाजन का उल्लंघन होगा। वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों के नामांकन को अनुमति देने वाले प्रावधान पर रोक नहीं लगाई गई है। न्यायालय ने कहा है कि जहाँ तक संभव हो, बोर्ड का पदेन सदस्य मुस्लिम व्यक्ति होना चाहिए। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि केंद्रीय वक्फ परिषद में चार से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे और राज्य वक्फ बोर्ड में तीन से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य शामिल नहीं किए जाएंगे। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि ये टिप्पणियाँ केवल प्रथम दृष्टया प्रकृति की हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी।

सेवा और सुशासन, मंत्र पर चलते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार परिवर्तन और प्रगति के लिए अथक प्रयास कर रही है। इन प्रयासों की सफलता से जुड़े 'सेवा पर्व' की विशेष शृंखला के क्रम में प्रस्तुत है एक रिपोर्ट—

भारत की पर्यावरणीय सद्भाव की यात्रा एक जीवित चित्रकला के रूप में उभर रही है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस प्राचीन ज्ञान को मजबूत और व्यावहारिक कार्यवाही में बदल गया है। हमारे लिए एनवायरमेंट ये आर्टिकल ऑफ फेट। पूरी सृष्टि को चलाने के लिए मिलकेंग ऑफ नेचर तक तो चल सकता है, एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर नहीं चल सकता। आज भारत में जंगली बाघों की जनसंख्या पूरी दुनिया में सबसे अधिक है एशियाई शेरों की जनसंख्या आठ सौ इक्यानबे तक पहुंच गई है जो पिछले एक दशक में सत्तर प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है वही चीते सात दशकों बाद भारत में लौटे हैं और भारतीय भूमि पर नए शावक पैदा किए गए हैं जो प्रमुख परियोजना चीता का हिस्सा है। भारत के पास अब इक्यानबे रामसर साइट्स है जो एशिया में सबसे अधिक है यह प्रवासी पक्षियों और नाजुक परिस्थित क्यों और सुरक्षित रखती है। भूमि पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक सौ बयालीस करोड़ से अधिक पेड़ लगाए गए हैं जो स्थिति को भावना से जोड़ते हैं इस बीच आवरण धीरे-धीरे बढ़ा है जो भारत के प्राकृतिक कार्बन सिंक में योगदान कर रहा है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ अक्षत विद्यान आकाशवाणी समाचार दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दिवाली तक जीएसटी सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा की थी। आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी जैसे चिकित्सा उपकरणों और दवाओं के लिए किए गए सुधारों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।

परिषद ने आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी से जुड़ी कई दवाईयों पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है, साथ ही मेडिकल, डेंटल और पशु चिकित्सा से जुड़ी मशीनों पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गई है। इसके अलावा, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर कर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। दृष्टि के साथ, आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज वाराणसी में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वाराणसी में पहले की तुलना में काफी विकास कार्य हुए हैं। केन्द्र और प्रदेश सरकार की प्राथमिकता हमेशा से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के विकास की रही है। बैठक में इन सभी कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस-यूपीआई उपयोगकर्ता अब एक दिन में 10 लाख रुपये तक के व्यक्ति-से-व्यापारी लेनदेन कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम-एनपीसीआई ने निर्धारित श्रेणियों में व्यक्ति-से-व्यापारी लेनदेन के लिए एकल लेनदेन सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। एक रिपोर्ट—

एनपीसीआई ने पिछले महीने प्रति लेनदेन सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया था, जबकि अधिकांश मामलों में कुल सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक कर दिया गया है। हालाँकि, व्यक्ति-से-व्यक्ति लेन देन की सीमा एक लाख रुपये प्रति दिन पर बरकरार रहेगी। वहीं, क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान अब प्रति लेनदेन 5 लाख रुपये तक किया जा सकता है, जो एक दिन में अधिकतम 6 लाख रुपये हो सकता है। समाचार कक्ष से करिश्मा राय।

महाराजगंज जिले में चौदह अक्टूबर से पचीस नवम्बर तक सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज पत्रकारों से बातचीत में दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खेल की संस्कृति को गांव-गांव तक पहुंचाने की सोच को साकार करने के लिए यह आयोजन किए जा रहे हैं।
